मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha365@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L-2/FBD/463/2020-22 /R.N.I. No. 2022007062

वेतन खर्च बचाने के लिये खट्टर सरकार कुछ भी कर सकती है 2
खिलाड़ियों का बहाल करो कोटा वरना सरकार पर चलेगा सोटा 4
द कश्मीर फाइल्स : लोगों को बांटने का खतरनाक खेल 5
भगतसिंह के विचारों को जानिए, उनके नाम पर अफ़वाहबाजियों से बचिए 6
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग व जिला उपायुक्त को भेजा लीगल नोटिस 8

वर्ष 36 | अंक 21 | फरीदाबाद | 3-9 अप्रैल 2022 | फोन-8851091460 | 3.00 ₹

लुभावनी घोषणाएं बिखेरने आए खट्टर

लाल खट्टर

तिगांव (म.मो.) घोषणावीर मुख्यमंत्री खट्टर बीते रविवार को तिगांव क्षेत्र में आये और करीब 1500 करोड़ की घोषणाएं जनता के बीच बिखेर गए। ऐसी अनगिनत घोषणाएं बीते सात साल में खट्टर महाशय कर चुके हैं। घोषणा करने में क्या जाता है ? 1500 करोड़ की कर लो या 15000 करोड़ की, किसने गिनना है और किसने पूछना है ? इस तरह की थोथी घोषणाओं और भ्रष्टाचार को सारा ज़िला हर तरह से भुगत रहा है। ग्रेटर फ़रीदाबाद की जिन सड़कों व सीवर आदि की घोषणा वे कर रहे हैं इसका पैसा वहां के निवासी वर्षों पहले सरकार को दे चुके हैं।

जनसभा के दौरान प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मुद्दा उस समय खुल कर सामने आ गया जब तिगांव के विधायक और रैली के संयोजक राजेश नागर ने मंच से कहा कि खट्टर अपने भ्रष्ट निकम्मे व लापरवाह अधिकारियों को आज ही यहां से अपने साथ ले जायें, ऐसे अधिकारियों की यहां कोई जरूरत नहीं है। जवाब में खट्टर ने कहा कि वे 15 दिन में इसकी जांच करके उन अधिकारियों का यहां से

तबादला कर देंगे। यदि आरोप सिद्ध हुए तो उन्हें जेल में ठोक देंगे। यद्यपि विधायक नागर ने दागी अधिकारियों की गिनती तो नहीं बताई थी फ़िर भी न जाने खट्टर ने कैसे कह दिया कि उन चार अधिकारियों की जांच करेंगे।

सवाल चार भ्रष्ट अधिकारियों का नहीं है, यहां तो सारा प्रशासन ही भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है। खट्टर जी चार भ्रष्टों की बात करते हैं, इसके बजाय वे यहां के केवल चार ईमानदार अफ़सरों के नाम ही बता दें। रही बात विधायक नागर की तो यहां मसला दूसरा ही है। इनकी सीधी टक्कर सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर से रहती है। गूजर के न चाहते हुए भी नागर विधायक तो बन गए लेकिन उनका कोई भी प्रशासनिक काम मंत्री जी होने नहीं देते। इसके चलते अफ़सरों की समस्या यह है कि वे किसकी तो मानें और किसकी न मानें।

जनसभा के मंच पर मोटे अक्षरों में नारा लिखा था, 'भ्रष्टाचार का काल मुख्यमंत्री मनोहर लाल' उनकी करनी को देखते हुए यह नारा खट्टर को शोभा नहीं देता। वास्तव में नारा तो यह होना चाहिये था कि भ्रष्टाचार का दलाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल अथवा भ्रष्टाचार का गट्ठर मनोहर लाल खट्टर। सर्वविदित है कि इस क्षेत्र में तैनाती पाने के लिये अधिकारीगण मोटी रिश्वतें अपने राजनीतिक आकाओं को देकर यहां आते हैं और तैनाती बनाये रखने के लिये लगातार साप्ताहिक अथवा मासिक भेंट पूजा चलती रहती है। इसी के चलते, पहले से चले आ रहे भ्रष्टाचार ने अब नई-नई ऊंचाईयां छू ली हैं, पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। खट्टर लाख मासूम बनने का प्रयास करें परन्तु यह जनता है जो सब कुछ जानती है।

स्वास्थ्य सेवाओं की नौटंकी

घोषणावीर खट्टर ने जनसभा स्थल से ही जादू का डंडा घुमा कर खेड़ी कलां, पाली व तिगांव की डिस्पेंसरियों में ऑक्सीजन प्लांट भी चालू कर दिये। बीते करीब दो साल से तिगांव में खड़ी हेल्थ सेंटर की जो बिल्डिंग जर्जर होने जा रही थी उसका भी उद्घाटन कर दिया। और तो और बीके अस्पताल परिसर में विदेशी भीख के पैसे से बने 96 बेड के कोरोना वार्ड का भी उद्घाटन कर डाला। उद्घाटन तो कर डाले पर इन दोनों जगह न कोई डॉक्टर है न कोई अन्य स्टाफ़।

तहसीलों में भ्रष्टाचार के लिये अर्जीनवीसों को दोषी माना

फ़रीदाबाद (म.मो.) तहसील में तहसीलदारों द्वारा तमाम तरह की रजिस्ट्रीयों आदि के नाम पर जो जनता को लूटा जाता है उसके लिये खट्टर सरकार अर्जीनवीसों को दोषी मानती है। यानी कि तहसीलदार उनके ऊपर बैठे डीआरओ, एसडीएम व डिप्टी कमिश्नर तो तमाम दूध के धुले हुए हैं। इन सब की तैनाती कराने वाले राजनेता तो और भी पाक-साफ़ हैं। इसलिये खट्टर ने तहसीलों से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिये अर्जीनवीसों का काम ही समाप्त कर दिया।

विदित है कि तहसील में किसी भी प्रकार का पंजीकरण कराने के लिये स्टैम्प पेपर पर पूरा प्रकरण किसी अर्जीनवीस द्वारा ही लिखा जाता है। लिखाई का यह काम हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिये बाकायदा सरकार द्वारा आयोजित एक परीक्षा पास करनी पड़ती है, उसके बाद ही वह दस्तावेज़ लिखने को अधिकृत होता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये अर्जीनवीस ही तहसीलदारों के लिये बिचौलिये की भूमिका निभाते हुए दिन भर रिश्वत की रकम एकत्र करके शाम को तहसीलदारों के घर पहुंचा देते हैं। रिश्वतखोरी का यह धंधा निहायत ही ईमानदारी से चलता है। तहसीलदारों द्वारा प्रति रजिस्ट्री रिश्वत की दर तय कर दी जाती है जिसे ये लोग वसूल कर उन्हें सही सलामत पहुंचा देते हैं।

सरकार द्वारा अर्जीनवीसों को लाइसेंस जारी करते वक्त दस्तावेज लिखाई के रेट तय कर दिये जाते हैं, लेकिन ये इतने कम होते हैं कि कोई भी अर्जीनवीस इन रेटों पर गुजर-बसर नहीं कर सकता। ऐसे में ये लोग लिखाई के नाम पर काफ़ी अधिक वसूली भी करते हैं। इसके अतिरिक्त दस्तावेज़ बनवाने वाले लोग कई बार कानूनी सलाह मशवरा भी इन्हीं लोगों से लेते हैं। जो अर्जीनवीस इस तरह

शेष पेज दो पर

संदर्भवश सुधी पाठक जान लें कि राज्य भर में अस्पतालों के स्टाफ की स्थिति क्या है ?

		स्वीकृत पद	तैनात	रिक्त	
डॉक्टर	-	4881	4063	818	
स्टाफ नर्स	-	4399	2168	2231	50 %
हेल्थ वर्कर	-	6539	5190	1348	
लैब तकनीकी	-	1260	545	715	56 %
फ़ार्मासिस्ट	-	1050	680	370	
रेडियोग्राफर	-	314	95	219	69 %
ऑप्थो सहायक	-	190	75	115	60 %

ऑपरेशन थियेटर में सर्जन को सहायता करने वाले स्टाफ की कोई पोस्ट इस राज्य में नहीं है और सर्जरी उपकरणों को साफ-सुथरा एवं किटाणु रहित करने वाला भी कोई स्टाफ नहीं है। यह काम झाड़ू-पोछा करने वाले सफाईकर्मियों से कराया जाता है। जाहिर है कि जब वे ओटी में काम करेंगे तो झाड़ू-पोछा तो नहीं ही करेंगे इसके अलावा ओटी में डॉक्टरों के साथ-साथ इन कर्मचारियों की कमाई तो ठीक-ठाक हो ही जाती है स्टेटस भी बढ़ जाता है।

जनहित का दावा करने वाली खट्टर सरकार की हकीकत जानने के लिये दिये गये आंकड़े, इनकी जन विरोधी करतूतों का पुख्ता सबूत हैं। ये तमाम आंकड़े इस वर्ष के बजट में प्रदर्शित किये गये हैं। समझना कठिन नहीं है जहां 50 से लेकर 69 प्रतिशत तक अस्पताल कर्मियों के पद खाली पड़े हों वहां पर इस तरह के उद्घाटनों का मतलब केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।